(b) Though individual exchanges can be loaded up to 84 per cent in a multi-exchange system at any point of time a loading of more than 85 per cent is considered satisfactory. This is due to (a) under-loading necessiated by wear and tear, (b) recent expansion whose utilisation is being executed, (c) capacity beyond 90 per cent is to be adjusted to last till the next expansion. Every effort is made to release maximum number of connections possible to meet the waiting list.

महाराष्ट्र में विदर्भ विकास बोर्ड

1711. **डा० रत्नाकर पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान में महाराष्ट्र के विदर्भ विकास बोर्ड के संबंध में कोई प्रावधान है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से विदर्भ विकास बोर्ड से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार उस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) विदर्भ विकास बोर्ड को कानूनी रूप देने के लिए संसद में विधेयक के कब तक लाए जाने की संभावना है और इस बोर्ड के कब तक गठित कर दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् । संविधान के अनुच्छेद 371(2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि विदर्भ मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक-पृथक विकास बोर्डों की स्थापना करने के लिए राष्ट्रपति आदेश द्वारा राज्यपाल को कोई भी विशेष जिम्मेदारी दे सकते हैं ।

(ख) उक्त अनुच्छेद के उपबंधों को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) इस मामले में किसी भी संसदीय विधान की आवश्यकता नहीं है ।

Migration of Government Employees from Kashmir

1712. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total number of State and Central Government employees who have by now migrated from Kashmir valley to Jammu and other places of the country in the wake of the secessionist violence in Kashmir;

(b) whether Government have been paying those employees their salaries and allowances;

(c) whether the employees are being given new postings in Jammu region till normalcy returns to Kashmir valley;

(d) whether any arrangements have been made for proper accommodation of the migrant employees in Jammu; and

(e) what arrangements have been made for the admission of the children of the migrant employees in schools and colleges?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (e) The Government of Jammu and Kashmir has advised that over 12,000 Government employees have been registered as migrants at Jammu. The number of registered migrant Government employees reported by Delhi Administration is over 3,000. The Central and Jammu & Kashmir